

प्रकाशनार्थ

पटना, 23 नवम्बर। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने आज आद्री परिसर में यूनिसेफ और आद्री के सहयोग से बाल बजट निर्माण प्रशिक्षण विषय पर एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विभागों यथा स्वास्थ्य, पंचायती राज, श्रम संसाधन और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में बाल बजट तैयार करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है। बिहार सरकार ने बाल बजट की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2013-14 से की थी।

सेन्टर फॉर इकोनाॅमिक पालिसी एंड पब्लिक फाइनांस (सीईपीपीएफ), आद्री की सहायक प्रोफेसर डा. बरना गांगुली ने विषय प्रवेश किया और कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होने विस्तार से बताया कि बाल बजट की प्रक्रिया वर्ष 2013-14 से लागू तो है परंतु अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं, जिन्हें एक मजबूत दस्तावेज बनाने के लिए दूर करने की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बजट अधिकारियों को बाल बजट दस्तावेज हेतु डेटा संकलन करने में दिशानिर्देश प्रदान करेगा।

तकनीकी सत्र-1 में वित्त विभाग के उप सचिव श्री संजीव मित्तल ने बजट निर्माण के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाल बजट मुख्य बजट का ही हिस्सा है इसलिए हमें लेखा शीर्ष के माध्यम से व्यय पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। तकनीकी सत्र-2 में वित्त विभाग के उप सचिव श्री अजय ठाकुर ने बाल बजट दस्तावेज में शामिल कार्यक्रमों के प्रकार पर प्रशिक्षण को केन्द्रित किया।

बिहार सरकार के विभिन्न 16 विभागों को यह प्रशिक्षण दिया जाना निर्धारित है। कोविड-19 की सावधानियों के मद्देनजर प्रत्येक चार-चार विभागों का एक बैच तैयार किया गया है। इस प्रकार चार बैच में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को बांटा गया है ताकि सामाजिक दूरी का पालन हो सके। इसी प्रकार, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वित्त विभाग, योजना, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन - 25 नवंबर, 2020, समाज कल्याण विभाग, कला, संस्कृति और युवा, स्वास्थ्य, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन - 27 नवंबर, 2020 और शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग-अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण - 30 नवंबर, 2020 को निर्धारित हैं।

आद्री के श्री सुदीप पांडेय ने स्वागत भाषण दिया और सीईपीपीएफ, आद्री के डा. रहबर अली ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

(अंजनी कुमार वर्मा)